आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को बनाया जा सके।
तथा आर्थिक पुनीकरण और उदारीकरण की नयी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

1 May 2020 D.El.Ed 2nd sem B.R.C Deoband
Thursday Amish Pro — Sapna Tyagi

आचार्य राममूर्ति समिति

एक समिति नीति पर नये सिरे से विचार करने के लिये भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा 1990 को समिति की घोषणा की गयी तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठा कि अभी पाँच वर्ष भी नहीं हुए फिर नयी कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। उस समय भारत के सामने प्रमुख रूप से बुनियादी चिन्तायें निम्नलिखित थी।

1 ⟶ काम का अधिकार जिसे संविधान में लिखने का प्रस्ताव सरकार के सामने है।
2 ⟶ राष्ट्र की एकता और अखण्डता जो गम्भीर खतरे में है।
3 ⟶ भारत के लोगों के दिलो में जो इन्सानियत है वह समाप्त होती जा रही है।
4 ⟶ समिति की अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर 1990 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी।

आचार्य राममूर्ति समिति ने सन् 1986 की "राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वस्तुनिष्ठ समीक्षा प्रस्तुत करते हुए भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।"

"इसमें तीन अध्याय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप।"
"शेष अध्यायो में केवल वास्तविक मुद्दे और उन पर सिफारिशें की गयी हैं"

यशपाल समिति 1992

भारत सरकार के विकास मन्त्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया — 1992 में
समिति के अध्यक्ष = प्रो० यशपाल

समिति का मुख्य उद्देश्य ⇒ पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक तैयार करना।
⇒ औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा में नवाचारों के प्रति समर्पित स्वैच्छिक शिक्षण प्रशिक्षण के विकास में स्वतन्त्रता तथा सहयोग।
⇒ नर्सरी स्कूल खोलने और उसके संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी व प्रशासनिक प्रयास किये जाये।

Scanned with CamScanner

→ छोटे बच्चों को भारी बस्ते के साथ प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए बाध्य करके उन्हें उत्पीड़न का कोई औचित्य नहीं है।

→ पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की 'सम्पत्ति समझा' जाए।

→ स्कूल में ही पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी जाये। वहीं रखी जानी चाहिए।

→ शिक्षक छात्र के वर्तमान 'अनुपात 1:40' को लागू किया जाए। प्राथमिक कक्षाओं में इसे घटाकर (1:30) किया जाए। इसी आधार पर 'शिक्षा की भावी योजना बनायी जाए।

→ भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए।

→ स्वास्थ्य तथा सफाई जैसे विषयों में कोरे उपदेशों के स्थान पर पाठ्य-पुस्तकों में यह सुनिश्चित किया जाय कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित अधिकांश विषय-वस्तु को ऐसे प्रयोगों एवं कार्यकलापों से जोड़ा जा सके, जिन्हें बच्चे एवं शिक्षक स्वयं करें।

⇒ इतिहास तथा भूगोल के अतिरिक्त छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में हमारी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के दर्शन तथा कार्यविधि की जानकारी दी जाय। ताकि छात्र सामाजिक, आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं और प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर उन्हें आत्मसात कर सके।

B.R.C. Deoband
ARP Bio- Sapna tyagi